paganda is not effective and how it could be made more effective.

SHRI P.G. SEN: It is well known that the Darjeeling Tea is the best tea. From recent newspaper reports, I find that the West Bengal Government has asked for release of two lakh acres which are now under tea gardens. How far will this affect Darjeeling tea which is the best tea produced?

SHRI B. R. BHAGAT: I have seen that report in the Press but I am not now in a position to say how it will affect Darjeeling tea production.

भारतीय दूतावासों में हिन्दी में सरकारी कार्य करना

*1415. **श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :**
कुमारी कमला कुमारी :
श्री नारायण स्वरूप शर्मा :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :

क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में भारत के ऐसे दूतावासों के नाम क्या हैं जहां सरकारी कार्य हिन्दी में किया जाता है ;

(ख) क्या सरकार का विचार उन दूतावासों में भी हिन्दी में कार्य आरम्भ करने का है जहां अभी तक हिन्दी में कार्य नहीं किया जाता ;

(ग) क्या सरकार का विचार भारतीय दूतावासों के उन अधिकारियों और कर्मचारियों को हिन्दी पढ़ाने का है जिनकी आयु 1 जनवरी, 1961 को 45 वर्ष से कम थी ; और

(घ) यदि हां, तो कब ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SURENDRA PAL SINGH): (a) and (b). While in a majority of Missions it is now possible to deal with relatively simple correspondence in Hindi, the transaction of official work in Hindi in Indian Missions will not be possible till such time as the availability of a larger number of personnel who could express themselves in Hindi with precision and fluency.

(c) and (d). Wherever possible, Hindi classes are arranged in Missions and personnel have also been advised to take advantage of the correspondence course inaugurated by the Central Hindi Directorate. As the teaching of Hindi is a continuous process, no fixed time limit can be set.

श्री राम स्वरूप विद्यार्थी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि हमारे राजदूत दूसरे देशों में अपने प्रमाण-पत्र पेश करते हैं तो वह हिन्दी में पेश करते हैं या अंग्रेजी में ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : प्रमाण-पत्र हिन्दी में होते हैं।

श्री रामस्वरूप विद्यार्थी : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि वे देश जिनकी भाषा अंग्रेजी नहीं है जैसे जर्मनी, फ्रांस, रूस या दक्षिणी अमरीकी देश, उनके साथ पत्र-व्यवहार करते हुए क्या हिन्दी का प्रयोग किया जाता है ? यदि नहीं किया जाता है तो उसका क्या कारण है जबकि उन देशों की भाषा अंग्रेजी नहीं है ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, जिन मुल्कों की भाषा अंग्रेजी नहीं है बल्कि उनकी अपनी भाषा है उनके साथ अमूमन हमारा पत्र-व्यवहार अंग्रेजी में रहता है क्योंकि वहां पर हिन्दी का प्रयोग नहीं है। अंग्रेजी तो तब भी कुछ जानते हैं।...(**व्यवधान**)...

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री : मैं जानना चाहता हूं कि हमारे राजदूत, राजनयिक, प्रतिनिधि, प्रधान मंत्री, उप-प्रधान मंत्री तथा दूसरे मंत्रीगण जब विदेशों में जाते हैं तो क्या और देशों के मिशंस की तरह वहां अपने देश की भाषा में बोलते हैं या विदेशी भाषा में बोलते हैं—विशेष रूप से जबकि भारतीय लोगों में बोलना हो तब किस भाषा में बोलते हैं ?

मैं दूसरी बात यह जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार विदेशों में जाने वाले सर्विस के लोगों के लिए अंग्रेजी में प्रवीणता होना आवश्यक है, क्या उसी तरह से हिन्दी का ज्ञान भी होना आवश्यक है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : जहां तक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा सैलेक्शन का सवाल है, उसके बारे में सदन को पूरी जानकारी है। अपने मंत्रालय में हम कोशिश कर रहे हैं कि हिन्दी पढ़ने की पूरी सुविधा दी जाये ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हिन्दी जान सकें। हम इसके लिए भी प्रयत्नशील हैं कि हमारे यहां से जो पत्र-व्यवहार अंग्रेजी के अलावा और भाषाओं में होता है, उसको हम हिन्दी में करें और आवश्यकता हो तो वहां ट्रांसलेशन भी भेज सकते हैं।

जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि हमारे प्रधान मंत्री या दूसरे मंत्रीगण जो बाहर जाते हैं वे किस भाषा में बोलते हैं, तो वहां पर जैसा अवसर होता है वैसा करते हैं— अगर वहां पर भारतीय नागरिकों को बीच में बोल रहे हैं और ज्यादातर भारतीय नागरिक हिन्दी-भाषी क्षेत्र के हैं तो हिन्दी में बोला जाता है और अगर हिन्दी-भाषी क्षेत्र के नहीं हैं तो फिर ऐसी जबान में बोला जाता है, अंग्रेजी में, जिसको वे समझ सकें।

जहां तक उन देशों के लोगों से बात करने का सवाल है, अगर उस देश की भाषा भिन्न हुई तो फिर जैसी वहां पर ट्रांसलेशन की सुविधा हो उसी के हिसाब से बात करते हैं।

SHRI S. KANDAPPAN: Sir, even from a mediocre Government like the Government of India, we do not expect this kind of a measure. It is most shocking that where it is not wanted, Hindi is being imposed. I would like to know from the Government what is the purpose and what is the intention of the Government in issuing a directive to the embassies that they should go on increasing the use of Hindi in their day-to-day administration and in their contact with the people in those countries and also in the instruction issued by the Government that they should have a specified dress to wear on ceremonial occasions and all this kind of thing. I would like to know whether it is the intention of the Government to project an image abroad that Hindi is the only language in India and Hindi represents the culture that is the prevalent culture in India. If that is the intention, we are totally opposed to it, and it is most unfair for a polyglot and multilingual country like ours. (*Interruption*). We have got enough problems in the country without Hindi and so let us not add to them. We know the diplomatic bungling of this Government and the inefficiency of this Government to gear up the working of our embassies.

MR. SPEAKER: You have asked the question: whether it is the desire to project the Hindi culture.

SHRI S. KANDAPPAN: In order to sidetrack the people and to throw mud in their eyes so as not to see the diplomatic bungling of this Government, the Government, I feel, is indulging in this kind of foolhardy venture. So, I would like to know this. Instead of wasting our resources like this and also giving a feeling to the non-Hindi people in this country that their culture is not being properly represented abroad, I would like to know from the Government whether they will see to it that they put the embassies in the job for which they are intended.

SHRI DINESH SINGH: I entirely agree with the hon. Member that we should not project any further conflict, and therefore, there is no question of our wanting to impose Hindi. Obviously, if it is a question of giving an impression to the world as to what is the working language, then we are gradually encouraging Hindi as the working language. That is quite clear. I would like to assure him that there is no need for him to worry that we are imposing Hindi as such.

SHRI S. KANDAPPAN: He is alienating even the Indians who are living abroad. He is side-tracking the issue. The Embassies in Delhi, whether American or Russian, and the Ambassadors and Attaches there try to learn the Indian

languages and try to cultivate the people here. That is diplomacy. But in our Embassies abroad, instead of learning the languages of those countries where our Embassies are situated—German or French or whatever it may be—you are trying to impose your language. Naturally, the consequence would be you are alienating the people there and not cultivating them. And also the Indians living abroad speak various languages like Bengali, Tamil, etc. Instead of cultivating them, you are trying to scare them away.

श्री द्वा० ना० तिवारी : अध्यक्ष महोदय, आफ़िशियल लैंगुएज ऐक्ट पास होने के बाद ऐसी धारणा हो चली थी कि हिन्दी आफ़िशियल लैंगुएज हुई और जब तक देश के दूसरे भागों के लोग हिन्दी में पूरे पारंगत न हो जायें तब तक अंग्रेजी भी साथ-साथ चले। पर क्यों? इस हाउस में कभी-कभी हिन्दी का नाम सुन कर लोग उबल पड़ते हैं, मैं जो बात जानना चाहता हूँ वह यह कि क्या यह इंस्ट्रक्शन्स ऐम्बेसीज़ को भी दिये गये कि हिन्दी के साथ-साथ अंग्रेजी रहे लेकिन हिन्दी का इस्तेमाल जरूर हो?

दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि जब फौरेन डिगनीटरीज़ इस देश में आते हैं, जैसे चीनी, रूसी आदि, या किसी अन्य देश के, तो वह अंग्रेजी जानते हुए भी जब यहाँ भाषण देते हैं तो अपनी भाषा में देते हैं और उनका ट्रांसलेशन इंगलिश में होता है। क्या हमारे यहाँ के लोग भी ऐसा ही करेंगे कि हिन्दी में भाषण दें और उसका ट्रांसलेशन अंग्रेजी में हो?

श्री दिनेश सिंह : जहाँ तक नीति का सवाल है अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो कहा, सरकार की जो नीति है वही नीति का हम पालन कर रहे हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं है।

जहाँ तक बाहर जाने वाली बात है हमारे मंत्रीगण किस भाषा में बोलें, मैंने अर्ज़ किया कि वहाँ जो ट्रांसलेशन की फैसेलिटीज़ होती हैं उसको देखकर औपचारिक ढंग से हम काम करते हैं। हिन्दी तो धीरे-धीरे अपने-आप आने की बात है, उसको लादने या रोकने की कोई बात नहीं है।

SHRI D. N. TIWARI: I asked whether instructions have been issued to our Embassies to introduce Hindi along with English.

श्री दिनेश सिंह : हमने अपने मिशनों को कहा है यह तो जवाब में ही दिया हुआ है।

SHRI HEM BARUA: In view of the fact that most of the Indian diplomats and personnel working in our Missions abroad do not know Hindi, what are the reasons on account of which the Government are insisting on the use of Hindi, although English is one of the link languages adopted by this Parliament?

SHRI DINESH SINGH: If the hon. Member had followed the reply which my colleague gave, he would not have these doubts.

श्री मृत्युञ्जय प्रसाद : मैं एक ही बात जानना चाहूँगा कि विदेशों में जहाँ अंग्रेज़ी भाषा मातृभाषा नहीं है वहाँ क्या आप हिन्दी और अंग्रेजी दोनों छोड़कर उनकी भाषा में उनसे पत्राचार करते हैं या नहीं? उनके यहाँ उनकी भाषा में व्यवहार करते हैं या नहीं? या केवल अंग्रेजी में करते हैं?

श्री दिनेश सिंह : जैसी आवश्यकता होती है वहाँ की भाषा में भी हम पत्र-व्यवहार करते हैं।

SHRI H. N. MUKERJEE: Sir, I can understand the Government's interest in Hindi even though I do not appreciate its somewhat niggardly attitude towards the other Indian languages. But how does the Government reconcile its preoccupation with the promotion of Hindi as a medium of international intercourse with the idea that we should have and must have—and surely the Government also has said that our diplomatic services have got to be manned for as long a period as we can

envisage by people who belong in a majority to the non-Hindi-speaking areas and who would be in the present dispensation at a certain disadvantage because the use of Hindi makes the position of a non-Hindi-speaking person somewhat that of a second-rate officer in the set-up—persons from non-Hindi-speaking areas ? How does Government reconcile its preoccupation with Hindi to a certain extent even in relation to international affairs with its duty and responsibility of securing proper representation in the diplomatic sphere of our country?

SHRI DINESH SINGH: The people from non-Hindi-speaking area will suffer no disadvantage There is no attempt to impose Hindi in any way in which there will be any kind of disadvantage. I would beg of the hon. Member to again read the reply given by my colleague which makes the point quite clear.

SHRI J. B. KRIPALANI: Sir, in no Embassy any other language but English is used. Why are they so much bothered about it?

श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय विदेश मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि स्वतन्त्रता के पश्चात् अभी तक विदेशों में ऐसे कितने समारोह हुए या कितने अवसरों पर हमारे मन्त्रियों ने या प्रधान मंत्री या विदेश मंत्री ने अंग्रेजी के अलावा कभी किसी दूसरी भाषा का इस्तेमाल किया है ?

श्री दिनेश सिंह : मैं निश्चित रूप से कह नहीं सकता क्योंकि हमने कोई हिसाब नहीं रखा है।

श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : अगर नहीं मालूम है तो टेबिल पर रखें पूरी जानकारी हासिल करने के बाद।

श्री दिनेश सिंह : मैंने कहा इसका कोई हिसाब नहीं रखा है। मैंने पहले इसका जिक्र किया है कि जहाँ जैसी स्थिति होती है, जहाँ हिन्दी भाषी हों वहाँ प्रधान मंत्री जब गयीं तो हमेशा हिन्दी में भी स्पीच की, अंग्रेजी में भी की।

DR. M. SANTOSHAM: Sir, it is well known that more than half of our population abroad—in countries like Ceylon, Burma, Malaysia and African countries—are Tamilians. Therefore, I would like to ask the Minister, why not give parity to Tamil along with Hindi in those missions?

MR. SPEAKER: What about Bengali, Telugu and others?

SHRI S. KANDAPPAN: When the Prime Minister goes to Ceylon the Tamilians there gather to hear her (*Interruption*).

SHRI DINESH SINGH: In areas where we have people of Indian origin predominantly speaking Tamil, we try to keep an officer in the Mission who understands Tamil and can discuss with them in Tamil.

श्री म० ला० सोंधी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय बतायेंगे कि उनको पता है कि स्पेन के राजदूत ने अपना परिचय-पत्र हिन्दी में प्रस्तुत किया था ? तो क्या स्पेन के साथ भारत सरकार हिन्दी में कार्यवाही करने के लिए राजी है ?

MR. SPEAKER: I thought Shri Sondhi was particular in putting a question in Hindi and not about the answer.

SHRI H. N. MUKERJEE: Sir, the same question appears elsewhere independently on the list today.

श्री दिनेश सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी इसके पहले जिक्र किया था कि जो हमारे मंत्रालय से यहाँ पत्र व्यवहार होता है, जो अंग्रेजी में पत्र व्यवहार होता है उसका हम अंग्रेजी में जवाब देते हैं। जो पत्र व्यवहार अपने देश की भाषा में लोग करते हैं हम उसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि यथासम्भव हम उसका जवाब हिन्दी में दें।

श्री सरजू पाण्डेय : हिन्दी राज भाषा स्वीकार की जा चुकी है फिर भी अपने देश में और बाहर के देशों में भी हिन्दी में काम नहीं

हो रहा है और जिसे कि खुद मंत्री जी ने स्वीकार किया है तो मैं जानता हूं कि इस बात को देखते हुए कि हिन्दी जोकि इस देश की राज भाषा स्वीकार की गई है तो तमाम दूतावासों में और अपने देश में भी हिन्दी में कारोबार शुरू करने के लिए सरकार कोई निश्चित कदम उठा रही है अथवा नहीं ?

श्री दिनेश सिंह : इसका जवाब मेरे साथी ने दिया था ।

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

काश्मीर के सम्बन्ध में रूस की नीति

*1414. **श्री जि० ब० सिंह :**
श्री शारदानन्द :
श्री ओंकार सिंह :
श्री ओगोपाल साबू :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि काश्मीर के बारे में रूस का अब भी वैसा ही रुख है जैसा यह श्री ख्रुश्चेव के समय था;

(ख) यदि नहीं, तो इसमें कहां तक परिवर्तन हुआ है;

(ग) सरकार द्वारा गत एक वर्ष में रूस के नेताओं के साथ काश्मीर के बारे में हुई बातचीत का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या रूस अभी भी काश्मीर को भारत का अभिन्न अंग मानता है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (घ). सोवियत संघ ने 1955 में यह घोषणा की थी कि जम्मू और काश्मीर राज्य भारत गणराज्य के राज्यों में से एक है। सोवियत सरकार ने हमें बार-बार यह आश्वासन दिलाया है कि काश्मीर के विषय में उनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया है ।

काश्मीर के विकास के बारे में गजेन्द्र गडकर आयोग का प्रतिवेदन

*1416. **श्री ओम प्रकाश त्यागी** : क्या **प्रधान मन्त्री** 18 दिसम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5021 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने जम्मू तथा काश्मीर सरकार को वर्ष 1968-69 की वार्षिक योजना के लिए कितनी राशि दी है ;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा अन्य किन राज्यों की वार्षिक योजनाओं के लिए पूर्ण रूप से वित्त उपलब्ध किया जायेगा ; और

(ग) यदि केन्द्र द्वारा अन्य किसी राज्य की वार्षिक योजना के लिए पूरा वित्त उपलब्ध नहीं किया जा रहा है तो जम्मू तथा काश्मीर की वार्षिक योजना के लिए पूरा वित्त उपलब्ध करने के क्या कारण हैं ?

प्रधान मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) 21.70 करोड़ रुपये ।

(ख) असम, नागालैंड और राजस्थान ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

पाकिस्तान द्वारा सैनिक तैयारियां

*1417. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
श्री शिवकुमार शास्त्री :

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान की सैनिक तैयारियों के बारे में कोई नवीन जानकारी प्राप्त हुई है ;

(ख) क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने भारत की सीमाओं पर अपनी सैनिक तैयारियां और अधिक तेज कर दी हैं ; और